

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 जनवरी 2019—पौष 14, शक 1940

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से. (2000), अपर आयुक्त, रायपुर संभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, बस्तर संभाग (उन राजस्व प्रकरणों के अपील सुनवाई हेतु जिनमें मूल आदेश वर्तमान संभागायुक्त व पूर्व कलेक्टर, बस्तर द्वारा पारित किए गए हैं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27 नवंबर 2018

क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-54-03/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2018/1699ए, दिनांक 16-11-2018 द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार नगरपालिका परिषद् रतनपुर जिला बिलासपुर के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में दिनांक 31 दिसंबर, 2018 दिन सोमवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा.

2. अतएव राज्य शासन एतद्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका परिषद् रतनपुर, जिला बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 31 दिसंबर, 2018, दिन सोमवार को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

3. क्रमांक एफ 1-3/2014/1/5 राज्य शासन एतद्वारा, यह भी घोषित करता है कि, नगरपालिका परिषद् रतनपुर जिला बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कार्यालयों में दिनांक 31 दिसंबर 2018, दिन सोमवार को मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. राठिया, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2018

क्रमांक ई 7-10/2013/एक-2.—श्री रजत बंसल, आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को दिनांक 03-11-2018 से दिनांक 14-12-2018 तक 43 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर, 2018 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बंसल आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश काल में श्री बंसल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बंसल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2018

क्रमांक ई 7-15/2007/एक-2.—श्री देवी दयाल सिंह, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 28-11-2018 से दिनांक 07-12-2018 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08 एवं 09 दिसम्बर 2018 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवी दयाल सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 5-4/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरडिया, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 28 सितम्बर, 2018 से 01 अक्टूबर, 2018 तक कुल 04 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 02-10-2018 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

2. माननीय न्यायमूर्ति को दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 से 02 नवम्बर, 2018 तक कुल 05 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 03 नवम्बर, 2018 से 11 नवम्बर, 2018 (सार्वजनिक/दीपावली अवकाश) का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कन्नौजे, उप-सचिव.

### गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ 7-11/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला, (भापुसे-2011), पुलिस अधीक्षक, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़ को दिनांक 24-12-2018 से दिनांक 29-12-2018 (कुल 06 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है। साथ ही दिनांक 23 एवं 30-12-2018 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जिला-बालोद के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।

3. अवकाश काल में श्री एलेसेला को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एलेसेला (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

5. श्री इंदिरा कल्याण एलेसेला (भापुसे-2011), पुलिस अधीक्षक, जिला-बालोद, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उसका चालू प्रभार श्री झाड़ूराम ठाकुर, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला-बालोद को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लीना कमलेश मंडावी, उप-सचिव.

### वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 1-50/2001/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय वन सेवा के उप वन संरक्षक संवर्ग के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान प्राप्त अधिकारी श्री एम. गोविन्द राव, भा.व.से. (1998) को प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 01-09-2012 में की गई अनुशंसा, के अनुसार, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (2) (i) (iii) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार दिनांक 01-01-2012 से प्रवर श्रेणी वेतनमान पे बैंड 4, रुपये 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रुपये 8700/- में नियुक्त करता है।

रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 1-08/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय वन सेवा के उप वन संरक्षक संवर्ग के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान प्राप्त अधिकारी श्री आर. के. तिवारी, भा.व.से. (1998) को प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति हेतु छानबीन समिति की बैठक दिनांक 17-10-2017 में की गई अनुशंसा के अनुसार, भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (2) (i) (iii) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार दिनांक 01-01-2012 से प्रवर श्रेणी वेतनमान पे बैंड 4, रुपये 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रुपये 8,700/- में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**विजय कुमार चौधरी**, अवर सचिव.

### कृषि एवं जैव प्राद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्रमांक/8242/एफ-12/16/2009/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, घोषित करती है कि इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15/5/87/बी-14/3, दिनांक 9 दिसम्बर, 1987 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, कटघोरा के मण्डी प्रांगण में निम्नलिखित स्थान, जिसके अन्तर्गत समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आते हैं, उप-मण्डी प्रांगण होगा, अर्थात् :—

#### स्थान

ग्राम भैंसमा, तहसील कोरबा, जिला कोरबा, पटवारी हल्का नम्बर 09 में खसरा क्र. 284/1 की लगभग 1.50 एकड़ भूमि क्षेत्र की सीमायें निम्नानुसार है :—

- |    |            |   |   |
|----|------------|---|---|
| 1. | उत्तर में  | — | सड़क एवं श्री सरवन सिंह की भूमि         |
| 2. | दक्षिण में | — | श्री जोहन सिंह एवं श्री मन्दलाल की भूमि |
| 3. | पूर्व में  | — | शासकीय भूमि                             |
| 4. | पश्चिम में | — | सड़क                                    |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. सी. पैकरा**, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्रमांक/8242/एफ-12/16/2009/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/8242/ रायपुर, दिनांक 13-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**के. सी. पैकरा**, संयुक्त सचिव.

Raipur the 13th Decembper 2018

No./8242/F-12/16/2009/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the state Government, hereby declares that the following places including all structures, enclosures, open place or locality shall be sub-market yard in the market yard of Krishi Upaj Mandi Samiti, Katghora vide this department's Notification No. D-15/5/87/B-14/3, dated 09th December 1987 namely :—

## PLACE

Boundaries of an area about 1.50 Acre land of Khasra No. 284/1 at Village Bhaisma Patwari Halka Number 09 in Korba Tehsil of Korba District are as under :—

- |    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
| 1. | In North side | — | Road and land of Shri Sarwan Singh        |
| 2. | In South side | — | Land of Shri Johan Singh and Shri Mandlal |
| 3. | In East side  | — | Government land                           |
| 4. | In West side  | — | Road                                      |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्रमांक/8250/एफ-11/10/2018/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि निम्नलिखित स्थान, जिसके अंतर्गत मंडी प्रांगण की समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, जिसके लिये इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2183/8954/14-1, दिनांक 26 अप्रैल, 1969 द्वारा मण्डी स्थापित की गई है, किसान/उपभोक्ता उप-मण्डी प्रांगण होगा, अर्थात् :—

## स्थान

ग्राम बैकुण्ठपुर (चेरवापारा), जिला कोरिया में खसरा क्रमांक 825/1 की लगभग 0.089 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमायें निम्नानुसार हैं :—

- |    |                 |   |                              |
|----|-----------------|---|------------------------------|
| 1. | उत्तर दिशा में  | — | कृषि उपज मण्डी की भूमि       |
| 2. | दक्षिण दिशा में | — | राष्ट्रीय राजमार्ग 43        |
| 3. | पूर्व दिशा में  | — | छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग |
| 4. | पश्चिम दिशा में | — | कृषि उपज मण्डी की भूमि       |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्रमांक/8250/एफ-11/10/2018/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/8250/रायपुर, दिनांक 13-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Raipur the 13th Decembper 2018

No./8250/F-11/10/2018/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhinniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, declares that the following places including all structures enclosures, open place or locality in the market yard for which a market has been established by the department's Notification No. 2183/8954/14-1, dated 26th April, 1969, shall be farmer/consumer sub market yard namely :—

## PLACE

Boundaries of an area about 0.089 hectare land of khasra No. 825/1 at Village Baikunthpur (Chervapara), District Koriya are as under :—

- |    |               |   |   |
|----|---------------|---|---|
| 1. | In North side | — | Land of Krishi Upaj Mandi                     |
| 2. | In South side | — | NH 43   |
| 3. | In East side  | — | Government of Chhattisgarh Revenue Department |
| 4. | In West side  | — | Land of Krishi Upaj Mandi                     |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/18736/क/भू-अर्जन/01 अ 82/2018-19.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	उरगा	0.790 हे. 1.95 ए.	चाम्पा-गेवरा रेलमार्ग (उरगा के पास) रेलवे ओव्हर ब्रिज के पहुंच मार्ग निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 19-01-2019 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम उरगा नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण                | — | चाम्पा-गेवरा रेलमार्ग (उरगा के पास) रेलवे ओव्हर ब्रिज के पहुंच मार्ग निर्माण. |
| 2. | प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या  | — | 27  |
| 3. | अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या | — | निरंक   |

4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों— की अनुमानित संख्या.	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	— निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	— हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	— हां
8.	परियोजना की कुल लागत	— 2828.00 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	— आवागमन की सुविधा
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथ उस पर होने वाला संभावित व्यय.	— प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	— निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर  
(1)  
रकबा  
(हेक्टेयर में)  
(2)

महासमुन्द, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

क्रमांक/105/क/भू-अर्जन/04/अ/82/2016-17.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-पिथौरा

(ग) नगर/ग्राम-सागुनढाप तु.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.18 हेक्टेयर

2	0.78
6	0.11
3	0.65
5	0.28
21	0.22
23	0.21
25	0.23
27	0.07
7	0.11
9	0.35
10	0.41
8	0.15
29	0.04
4	0.16
26	0.17
24	0.16
22	0.06

		(1)	(2)
		30	0.02
योग	18	4.18	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लॉवरजॉक बैराज योजना हेतु.		85/1	0.34
		141	0.44
		86	0.16
		89	0.51
		170	0.02
		87	0.33
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.		90	0.34
		171	0.09
		91	0.36
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		175	0.47
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		168	0.14
		92	0.33
		101/1	0.01
महासमुंद, दिनांक 31 दिसम्बर 2018		101/6	0.05
		176/4	0.10
क्रमांक/108/क/भू-अर्जन/03/अ/82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		101/2	0.03
		101/5	0.08
		101/3	0.09
		176/1	0.01
		101/4	0.08
		176/3	0.10
		102	0.22
		142	0.06
		103	0.22
		143/2	0.20
		143/3	0.16
		104/2	0.02
(1) भूमि का वर्णन—		177/1	0.01
(क) जिला-महासमुन्द		177/3	0.08
(ख) तहसील-पिथौरा		177/2	0.18
(ग) नगर/ग्राम-सागुनढाप तु. राजाकटेल		172	0.17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.28 हेक्टेयर		144/1	0.22
		144/2	0.06
खसरा नम्बर	रकबा	133/10	0.14
	(हेक्टेयर में)	133/15	0.03
(1)	(2)	133/12	0.07
62	0.36	133/11	0.22
58	0.08	133/13	0.13
83	0.10	133/16	0.12
63	0.31	133/14	0.05
57	0.02		
80	0.11	योग	52
66/2	0.08		8.28
66/4	0.10	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लॉवरजॉक बैराज योजना हेतु.	
82	0.10	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
64	0.20		
65	0.18		
81	0.20		



महासमुंद, दिनांक 31 दिसम्बर 2018		(1)	(2)
क्रमांक/109/क/भू-अर्जन/01/अ/82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		256	0.17
		255	0.17
		573/5	0.50
		252	0.30
		341	0.20
		572	0.12
		596	0.02
		609	0.18
		617	0.08
		330	0.15
अनुसूची		262	0.25
(1) भूमि का वर्णन—		573/3	0.05
(क) जिला-महासमुन्द		585/1	0.22
(ख) तहसील-पिथौरा		254	0.17
(ग) नगर/ग्राम-सांकरा		363	0.28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.09 हेक्टेयर		331	0.28
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	332	0.20
		458	0.58
(1)	(2)	313/1	0.28
		459	0.10
		370	0.34
309	0.08	340	0.03
314	0.20	594	0.18
436/1	0.33	432	1.08
436/59	0.15	259	0.18
351	0.08	592/1	0.20
433/1	0.53	343	0.80
428/1	0.12	310	0.30
428/2	0.28	429	0.40
260	0.40	430	0.09
338	0.30	431	0.08
371	0.04	362	0.28
372	0.10	589/1, 589/2	0.02
352	0.02	368	0.08
329	0.03	353	0.25
339	0.12		
574	0.28	योग	62 13.09
591	0.24		
616	0.12		
433/3	0.01		
369/1, 369/2, 369/3	0.33		
427	0.08		
311/2	0.24		
311/1	0.06		
570	0.16		
595	0.18		
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लॉवरजॉक बैराज योजना हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग		(1)	(2)
रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2018		175/1	0.072
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 44/अ-82/17-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		87/3	0.040
अनुसूची		77/2	0.025
(1) भूमि का वर्णन—		173/1	0.142
(क) जिला-रायगढ़		175/5	0.076
(ख) तहसील-तमनार		181/3	0.001
(ग) नगर/ग्राम-गोढी		171/1	0.097
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.531 हेक्टेयर		169/2, 170/2	0.020
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	181/6	0.041
		180/2	0.064
(1)	(2)	175/2	0.016
42/1	0.122	181/7	0.086
46	0.016	175/3	0.072
38/1घ	0.040	226/2	0.139
38/1ख	0.051	227/1	0.138
45/9	0.080	256/2	0.235
47/7	0.027	229/1	0.016
47/8	0.027	259/1	0.040
47/9	0.026	236/1	0.093
47/10	0.026	47/1	0.001
47/11	0.026	236/3	0.061
47/12	0.027	257/4	0.061
47/13	0.027	258/1	0.057
48/1	0.011	511/7	0.058
50/7	0.015	511/8/ख	0.010
50/8	0.073	511/8/क	0.012
73/11	0.029	511/10	0.004
20/4	0.039	192/3, 193/3	0.020
20/14	0.020	511/9	0.045
73/2	0.113	513/3	0.040
74/2क	0.069	557/1	0.059
74/2ख	0.061	556/1	0.174
		552/5/क	0.140
		20/13	0.060
		26/7	0.040
		20/11	0.076
		74/2/ग	0.208
		190/2/ख, 191/2	0.001
		230/1	0.048
		225/1	0.011
		228/1	0.089
		552/5/ख	0.140
		553/1/ख	0.280
		553/3/ख	0.080
		553/2/ख	0.091
		26/8	0.022
		20/5	0.122
		227/2	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
190/3	0.049	275/10	0.089
553/3/क	0.060	275/6	0.192
553/2/क	0.050	256/1	0.817
		256/2	0.318
योग	72	262/2क	0.109
	4.531	261/1	0.114
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी.		275/7	0.089
तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन निर्माण हेतु.		262/3	0.008
		261/2	0.036
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		263/12	0.040
(रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.		263/11	0.060
		262/1	0.170
		250/6	0.437
		250/3	0.093
रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2018		246/3	0.202
		250/9	0.206
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/17-18.—चूंकि राज्य		244/1	0.336
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के		244/2	0.069
पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित		246/9	0.295
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन,		246/7	0.169
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का		250/4ख	0.031
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013		265/16	0.016
कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया		265/17	0.032
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		263/4क	0.023
		263/14	0.020
		265/15	0.073
अनुसूची		250/4ज	0.114
(1) भूमि का वर्णन-		264/1	0.101
(क) जिला-रायगढ़		264/2	0.072
(ख) तहसील-तमनार		263/13	0.040
(ग) नगर/ग्राम-बरकसपाली		247	0.056
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.607 हेक्टेयर		250/8	0.178
		279	0.144
खसरा नम्बर	रकबा	263/4/छ/6	0.017
	(हेक्टेयर में)	263/4/छ/5	0.017
(1)	(2)	262/4/ख/1	0.024
		255/3	0.089
		254/3	0.024
277/2	0.611	254/6	0.028
277/3	0.076	254/7	0.020
278/5	0.012	255/5	0.012
263/10	0.036	258/1	0.052
238/1	0.004	254/4	0.056
265/12	0.042	258/2	0.052
263/4च	0.044	254/2	0.028
263/4/छ/4	0.017	254/5	0.069
255/2	0.043	255/1	0.049

(1)	(2)
255/4	0.072
250/2	0.364
योग	58
	6.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 50/अ-82/17-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हेपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.124 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
296	0.089
297/1	0.101
299/3	0.146
299/4	0.045
331/1	0.074
310	0.036
330/2	0.036
315/2	0.190
315/3	0.046
319/2	0.127
327	0.013
341/1	0.067

(1)	(2)
319/1	0.008
331/2	0.073
331/3	0.073
योग	15
	1.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), घरघोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51/अ-82/17-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कोटरीमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.470 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
348/1	0.058
360	0.474
362/2	0.047
362/1	0.073
362/3	0.028
363	0.028
441	0.091
447	0.156
351/1	0.105
416/2	0.311
416/4	0.120

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

महासमुंद, दिनांक 21 दिसम्बर 2018

क्रमांक 724/क/वि-स्था/2018.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम आठ एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं हिम शिखर गुप्ता, कलेक्टर, जिला महासमुंद कैलेण्डर वर्ष 2019 हेतु जिला महासमुंद के समस्त शासकीय कार्यालयों, तथा संस्थाओं के लिए निम्नांकित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्रमांक	स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	दिन
1.	गणेश चतुर्थी	02 सितम्बर 2019	सोमवार
2.	दशहरा (महानवमी)	07 अक्टूबर 2019	सोमवार
3.	अन्नकूट (गोवर्धन पूजा)/दीपावली का दूसरा दिन	28 अक्टूबर 2019	सोमवार

उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा.

हिम शिखर गुप्ता,  
कलेक्टर.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 30th November 2018

No. 91/L.G./2018/II-3-18/2007.—Shri D.L. Katakwar, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 02 days on 05-11-2018 & 06-11-2018 along with permission to remain out of headquarters from 04-11-2018 to 11-11-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 248 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th November 2018

No. 92/L.G./2018/II-2-16/2015.—Smt. Suman Ekka, Judge, Family Court, Korba, is hereby, granted earned leave for 06 days from 22-10-2018 to 27-10-2018 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 16-10-2018 till before the office hours of 29-10-2018.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+09 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 30th November 2018

No. 93/L.G./2018/II-3-11/2014.—Shri Vijay Kumar Ekka, District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 22-10-2018 to 27-10-2018 along with permission to remain out of headquarters from 18-10-2018 to 27-10-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 283 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th November 2018

No. 94/L.G./2018/II-2-24/2016.—Shri Alok Kumar, Additional Principal Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 06 days from 22-10-2018 to 27-10-2018 along with permission to remain out of headquarters from 17-10-2018 to 28-10-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 189 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th November 2018

No. 95/L.G./2018/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi I Additional Principal Judge, Family Court Raipur, is hereby, granted earned leave for 05 days from 25-10-2018 to 29-10-2018

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 275 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

---

Bilaspur, the 30th November 2018

---

No. 96/L.G./2018/II-3-35/2011.—Shri Abdul Zahid Qureshi, the then Special Judge (Atrocities), Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days from 23-08-2018 to 25-08-2018 along with permission to remain out of headquarters from 22-08-2018 to 26-08-2018 and earned leave for 02 days on 05-11-2018 & 06-11-2018 along with permission to remain out of headquarters from 04-11-2018 to 11-11-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 280 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th November 2018

No. 97/L.G./2018/II-2-43/2004.—Shri Prabhat Kumar Shastri, Judge, Family Court, Manendragarh, District-Koriya is hereby, granted earned leave for 03 days from 15-10-2018 to 17-10-2018 along with permission to leave headquarters from 13-10-2018 to 21-10-2018 and earned leave for 02 days on 05-11-2018 & 06-11-2018 along with permission to leave headquarters from 04-11-2018 to 11-11-2018

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 298 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 30th November 2018

No. 98/L.G./2018/II-3-13/2008.—Shri Rajesh Kumar Shrivastava, District & Sessions Judge, Janjgir- Champa is hereby, granted earned leave for 02 days on 22-10-2018 & 23-10-2018 along with permission to remain out of headquarters from 18-10-2018 to 23-10-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+01 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,  
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN).

---